***Date*:** 02-02-2022
***Publication*:** The Hitavada
***Edition*:** Jabalpur

CIL's output rises 7 per cent in Jan

NEW DELHI, Feb 1 (PTI)

STATE-OWNED CIL's production registered an increase of 6.7 per cent to 64.5 million tonnes (MT) in January.

The company's output in the corresponding month of the previous financial year had stood at 60.4 MT, Coal India Ltd (CIL) said in a filing to the BSE.

CIL's output in the April-January period of the current fiscal increased to 478.1 MT, over 453.2 MT in the year-ago period, the filing said.

Its supplies to the country's coal-fired power plants raced ahead to 441.4 million tonnes (MT) during April-January of FY22, the company said in a statement. This is a robust volume increase of 83 MT representing a 23 per cent growth compared to 358.2 MT despatch of the corresponding period last year.

The firm's current coal despatch trend to the power sector indicates that by the closure of FY22, the company shall comfortably surpass the previous high of 491 MT supplied to thermal power plants in FY19, the statement said. CIL is also aiming to overtake the ongoing fiscal's offtake target of 548 MT to the power sector. During the referred period, the company supplied around 80 MT more coal to all its customers as the total offtake evinced a steep increase to 542.4 MT, registering a 17 per cent year-on-year growth. Total offtake during the same period last year stood at 463 MT.

CIL produced 478 MT of coal till January of the current financial year, which is a 25 MT jump compared with 453 MT same period last year, posting 5.5 per cent growth. "Our coal output was hampered during the monsoon, which was extensive and extended but we still managed to register a 25 MT increase till January in absolute terms," the company said.

***Date*:** 05-02-2022
***Publication*:** Dainik Bhaskar
***Edition*:** Jaipur

प्रदेश को मिलेगा 7 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला : कोल इंडिया

जयपुर | प्रदेश की थर्मल पावर प्लांट को कोल इंडिया सात लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराएगी। कोल इंडिया से फिलहाल 8 रैक कोयला मिल रहा है। रैक की व्यवस्था होते ही करीब 11 रैक कोयला रोजाना मिलने लगेगा। इससे बाद प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट में कोयला संकट समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में कोयला संकट से निपटने के लिए शुक्रवार को कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल व अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इसी दौरान कोल इंडिया ने यह जानकारी दी।

- विस्तृत खबर पेज 7 पर

थर्मल पावर प्लांट को कोल इंडिया से मिलेगा 7 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला, नहीं खरीदनी होगी प्राइवेट बिजलीघर से बिजली

कोल इंडिया चेयरमैन की ऊर्जा विभाग के एसीएस के साथ मीटिंग

भास्कर न्यूज | जयपुर

प्रदेश की थर्मल पावर प्लांट को कोल इंडिया सात लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराएगी। इसके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी को अतिरिक्त रेलवे रैक का इंतजाम करना पड़ेगा। कोल इंडिया से फिलहाल 8 रैक कोयला मिल रहा है। रैक की व्यवस्था होते ही करीब 11 रैक कोयला रोजाना मिलने लगेगा। इसके बाद प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट में कोयला संकट समाप्त हो जाएगा तथा रबी फसल के लिए प्राइवेट बिजलीघर से महंगी रेट पर बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। प्रदेश में कोयला संकट से निपटने के लिए शुक्रवार को कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल व अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई।

प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट की 7580 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। जिसमें से 3240 मेगावाट उत्पादन क्षमता की कोटा, छबड़ा व सूरतगढ़ यूनिट के लिए कोल इंडिया से कोयला मिलता है। कोयला संकट के कारण जून 2021 में करीब 2448 मेगावाट उत्पादन रह गया था जो बढ़कर फरवरी 2022 में औसतन 6000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा विभाग के एसीएस के सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोल इंडिया ने एसईसीएल की दीपिका माइंस से 5 लाख टन और एनसीएल की खडिया माइंस से दो लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला मिलेगा। रेलवे से रैक की उपलब्ध बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि विदेशों से आयातित कोयले के दाम बढ़ने और देश में देर तक मानसून के चलते कोयले का संकट है। कोल संकट, मानसून और कोरोना के विपरीत हालात के बावजूद कोल इंडिया ने कोयले का 25 फीसदी अतिरिक्त उत्पादन कर कोयला उपलब्ध कराया। जिससे देश में 17 फीसदी बिजली उत्पादन की बढ़ोतरी हुई है। डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य में बिजली डिमांड, उपलब्धता और सप्लाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा ने बताया कि कोल इंडिया से संचालित तापीय विद्युत गृहों के लिए प्रतिदिन 11 रेक आपूर्ति की आवश्यकता है।

Date: 05-02-2022
Publication: The Hindu
Edition: Mumbai

THE HINDU

Coal India mulls bulk exports for first time

Energy crisis likely to delay shipments

REUTERS
BENGALURU

Coal India Ltd. (CIL), the world's largest coal miner, plans to directly export output to neighbouring countries, according to sources and documents seen by Reuters, after decades of exclusively supplying domestic consumers.

The state-run firm plans to export to Bangladesh, Nepal and Bhutan, according to a draft policy sent to the Secretary of India's Coal Ministry and reviewed by Reuters, as a part of India's 'neighbourhood-first' policy which seeks to counter China's growing economic influence in South Asia.

The proposal was confirmed by Coal India's chairman to Reuters this week, although a critical coal shortage in India now means the first such shipments would be unlikely until the end of this year. "We would have ideally wanted to start exporting this financial year (ending March 2022), if not for the energy crisis," Coal India Chairman Pramod Agrawal told Reuters.

***Date*:** 06-02-2022
***Publication*:** Hari Bhoomi
***Edition*:** Korba

कोल इंडिया खदानों में लगाएगी 4 कोल गैसीफिकेशन प्लांट

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

कोल इंडिया बढ़ते प्रदूषण को लेकर धीरे धीरे कोयले पर निर्भरता को कम करने को लेकर काम कर रहा है। कंपनी सौर ऊर्जा के साथ पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बॉड की तैयारी में है।

खास बात

- कोयला पर निर्भरता कम करने और पारंपरिक उर्जा को बढ़ावा देने की योजना

कोयला को सॉलिड फ्यूल की जगह गैसीय रुप में उपयोग करने के लिए 4 कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है।

उल्लेखनीय है कि कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सरफेस कोल गैसीफिकेशन और दूसरा भूमिगत कोल गैसीफिकेशन सरफेस कोल गैसीफिकेशन में प्लांट स्थापित कर कोयला लाकर कोल टू गैस बनाई जाती है। वहीं अंडर ग्राउंड कोल गैसीफिकेशन कोयला क्षेत्र में ही प्लांट स्थापित किया जाता है। भूमिगत कोयले से ही गैस बनाई जाती है और आपूर्ति की जाती है। सिफर के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जिस 4 कोल गैसीफिकेशन प्लांट की योजना बनाई गई है वह सरफेस कोल गैसीफिकेशन प्लांट है। कोयले पर निर्भरता कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने संबंधी योजना पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक दीर्घकालीन योजना है। सूत्रों की मानें तो फिलहाल दो दशक तक भारत में कोयले की उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर रुख रहेगा। वर्तमान में देश के पास कोयले का विकल्प नहीं है। 60 प्रतिशत पावर प्लांट कोयला आधारित है इसलिए बिजली आपूर्ति के लिए कोयला अहम स्रोत बना रहेगा। सूत्रों की मानें तो कोल इंडिया ने एमईसीएल और एसईसीएल में गैसीफिकेशन प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई है। हालांकि अभी इस कार्ययोजना पर अमल शुरु नहीं किया गया है।

***Date*:** 07-02-2022
***Publication*:** Dainik Jagran
***Edition*:** Dhanbad

कोल इंडिया को सोलर पैनल के लिए मिले ₹1400 करोड़

जासं, धनबाद : कोल इंडिया अब कोयला उत्पादन के सोलर दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर चुकी है। इसी का नतीजा है कि इस वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में राशि का अलाटमेंट भी सरकार ने कर दिया है।

सीआइएल 123 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन संयुक्त साझेदारी के तहत करेगी। सोलर एनर्जी के लिए कुल 1400 करोड़ रुपये सीआइएल को आवंटित कर दिया गया है।

विभागीय सूत्रों ने इस साल जारी बजट का हवाला देते हुए बताया कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जबकि छोटे स्तर पर कोल इंडिया रुफ टाप सोलर पैनल स्थापित कर सोलर एनर्जी का उत्पादन करेगी। बजट प्रस्ताव के अनुसार इसके लिए पीएलआइ योजना के तहत प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ताप उत्पादन में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पैलेट के प्रयोग के लिए इजाजत भी दी गई है।

बजट में प्रविधान : केंद्र सरकार कोल इंडिया के साथ अन्य पावर कंपनियों की साझेदारी में 19500 करोड़ रुपये की लागत से पनबिजली उत्पादन के लिए खर्च करने के लिए बजट में प्रविधान रखा है। इसमें पावर कंपनियों के साथ कोल इंडिया की साझेदारी हो सकती है।

123

मेगावाट पनबिजली व 27 मेगावाट सोलर एनर्जी का किया जाएगा उत्पादन

पर्यावरणीय क्लीयरेंस में नहीं होगी परेशानी

सूत्रों का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए हर प्रकार का पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेने के लिए अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके लिए परिवेश पोर्टल पर ही व्यवस्था करते हुए एकल खिड़की प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। जल्द ही इसके लिए इस पोर्टल पर प्रावधान कर दिया जाएगा।